Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 29 ◘ अंक- 87 ◘ रायपुर, मंगलवार 21 अप्रैल 2026 ◘ पृष्ठ-8 ◘ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

एनएच-130 पर चक्काजाम, कलेक्टर तक गुहार बेअसर

अब पुलिया निर्माण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर बैठे ग्रामीण

स्कूल ड्रेस में बच्चे भी हुए शामिल

गरियाबंद, 21 अप्रैल (हाईवे चैनल)। मैनपुर ब्लॉक के अमाड़ पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने मंगलवार को पुलिया निर्माण की मांग को लेकर नेशनल हाइवे-130 पर चक्काजाम कर दिया है. भारी संख्या में आश्रित ग्रामों की महिलाएं और स्कूली बच्चे जुगाड़ के पास पहुंचकर चक्का जाम कर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुल निर्माण के नाम पर पुराने रपटे को तोड़ दिया गया, जिससे आने वाले मानसून सीजन में ग्रामीणों की आवाजाही पर गंभीर असर पड़ सकता है. मांग की थी कि बारिश के पूर्व उनके मार्ग में तोड़े गए पुल को आवाजाही लायक ही बना दिया जाए, ताकि रोजमार्रा के काम और स्कूली बच्चों को आने-जाने में परेशानी ना हो, लेकिन सुस्त प्रशासन ने पहल नहीं की. इससे पहले 30 मार्च को ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर अपनी समस्या से अवगत कराया था।

इस नेशनल हाइवे पर बैठे ग्रामीणों के अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की सूचना कलेक्टर को 15 दिन पूर्व दी गई थी. बड़ी संख्या में स्कूल ड्रेस में बच्चे और महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर शामिल हुई हैं. अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम और लोकेश्वरी नेताम का कहना है कि प्रशासन आदिवासी अंचल के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है. उनका कहना है कि बारिश के दौरान स्कूली बच्चों और प्रसूताओं को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.

दरअसल, नेशनल हाईवे से अमाड़ को जोड़ने वाले मार्ग पर पट्टाबहाल नाले पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए वर्ष 2024 में विशेष केंद्रीय सहायता मद से 1.49 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली थी. इस कार्य के लिए पीएमजीएसवाय विभाग को एजेंसी बनाया गया और एमएस नमन कंस्ट्रक्शन से अनुबंध किया गया. ठेका कंपनी ने फरवरी माह में काम शुरू करते हुए पहले से मौजूद रपटे को तोड़ दिया और नींव की खुदाई भी शुरू कर दी थी. फिलहाल नाले पर केवल कच्ची मिट्टी और रेत से अस्थाई रपटा बनाया गया है, जो हल्की बारिश में बह जाने की आशंका है। हालांकि, उदंती अभ्यारण्य प्रशासन ने अनापत्ति प्रमाण पत्र का हवाला देते हुए काम रुकवा दिया. प्रशासनिक तालमेल के अभाव में निर्माण कार्य अधर में लटक गया, जिसका खामियाजा अब ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है. ऐसे में ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि बरसात से पहले कम से कम रपटे की मरम्मत कर आवाजाही सुचारू की जाए।

ईरान युद्ध के बीच भारत की आर्थिक रफ्तार बरकरार

जीडीपी ग्रोथ में बना एशिया का नंबर-1 देश, चीन भी रह गया पीछे

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (न्यूज चैनल)। संयुक्त राष्ट्र की संस्था United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान युद्ध और उससे पैदा हुए ऊर्जा संकट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इस वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिससे भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले साल भारत की ग्रोथ 7.4 प्रतिशत थी, जो इस साल थोड़ी कम होकर 6.4 प्रतिशत रहेगी, लेकिन अगले साल फिर बढ़कर 6.6 प्रतिशत हो सकती है। यह अनुमान उस समय के हालात पर आधारित है जब ईरान युद्ध चल रहा था और Strait of Hormuz पर असर पड़ने लगा था।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है। चीन की ग्रोथ इस साल 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि पाकिस्तान की ग्रोथ और कमजोर रह सकती है। इससे साफ है कि भारत क्षेत्र में सबसे आगे बना हुआ है। भारत की मजबूत ग्रोथ के पीछे घरेलू मांग, खासकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ता खर्च, सबसे बड़ा कारण बताया गया है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर जैसे आईटी और बैंकिंग भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार की नीतियां और गरीब वर्ग के लिए दी गई आर्थिक मदद ने भी बाजार में पैसा बनाए रखा। ईएससीएपी के अधिकारी हमजा मलिक के अनुसार, भारत की बढ़ती उत्पादकता और बड़ी आबादी उसकी आर्थिक मजबूती का बड़ा आधार है। इससे देश लंबे समय तक ऊंची ग्रोथ बनाए रख सकता है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं, जैसे अमेरिका को निर्यात में गिरावट और वैश्विक ऊर्जा संकट का असर। फिर भी, इन मुश्किलों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है और दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही है।

8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट: 18,000 से बढ़कर 34,000 तक सैलरी, 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (न्यूज चैनल)। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर नई अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर करीब 1.89 रहने की संभावना जताई जा रही है। जिसके लागू होते ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बदलाव देखने को मिल सकता है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर 1.89 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो यह मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर को सीधे प्रभावित करेगा। जैसे कि अगर किसी की मौजूदा न्यूनतम बेसिक पे 18,000 है तो वह बढ़कर संभावित नई बेसिक पे लगभग 34,000 हो जाएगी। इसका मतलब है कि लेवल-1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में करीब 16,000 तक का सीधा फायदा हो सकता है। कुल मिलाकर 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। नए वेतन आयोग के लागू होने पर मौजूदा महंगाई भत्ता (डीए), जो अभी करीब 60 प्रतिशत के आसपास पहुंच चुका है, उसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद डीए फिर से 0 प्रतिशत से शुरू होगा।

इंदिरा गांधी की तरह हैं प्रियंका गांधी': तेज प्रताप यादव

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (न्यूज चैनल)। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर कहा कि कांग्रेस की ओर से केवल वहीं हैं जो देश चला सकती हैं। वह भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह हैं। वह नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी से देश चलने वाला नहीं हैं। वह इधर उधर में फंसे रहेंगे।

बिरादरी की बात

चूहा- तेजप्रताप यादव राहुल की जगह प्रियंका गांधी को विपक्ष का नेता बनाने कह रहें हैं। चुहिया- हां जी, अब भाई-बहन में फूट डालकर आनंद उठाएंगे।

राइस मिल के गोदाम में लगी भीषण आग लाखों का धान और बारदाना खाक

कांकेर, 21 अप्रैल (हाईवे चैनल)। कांकेर जिले के कुलगांव में मंगलवार को अजीबो एग्रो राइस मिल में भीषण आग लग गई. घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. घटना में बड़ी मात्रा में बारदाना और धान को नुकसान पहुंचा है. पूरी घटना कोतवाली थाना इलाके की है।

जानकारी के मुतबाकि, सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है. वहीं मालिक मोहम्मद आवेश भी राइस मिल पहुंचे हैं. आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद जारी है. घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें धान के बोरों में लगी भ्यावह आग का मंजर नजर आ रहा है। राइस मिल मालिक मोहम्मद आवेश ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है. चांवल, धान और खाली बोरे सभी कुछ जल गया है. नुकसान का अभी आकलन नहीं किया जा सकता है।

महुआ बीनने गए ग्रामीण को हाथी ने उतारा मौत के घाट, क्षेत्र में दहशत

मनेन्द्रगढ़, 21 अप्रैल (हाईवे चैनल)। वन विभाग कि लापरवाही आई सामने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के जनकपुर पार्क परिक्षेत्र में एक बार फिर मानव-वन्यजीव संघर्ष की गंभीर घटना सामने आई है. जंगल में महुआ बिनने गए दंपति का हाथी से सामना हो गया. महिला ने किसी तरह दूर भागकर अपनी जान बचाने में सफल हुई, लेकिन हाथी के हमले में उसके पति की मौत हो गई. मृतक की पहचान प्रेमलाल के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, पति और पत्नी दोनों महुआ बिनने के लिए खोहरा बीट के जंगल गए थे. इसी दौरान अचानक एक जंगली हाथी ने उस पर हमला कर दिया. प्रेमलाल की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी नाराज़गी देखी जा रही है. सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं मृतक के परिजन को मुआवजा की राशि सौंपी गई है।

बताया जा रहा है कि घटना के काफी देर बाद तक वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे लोगों का आक्रोश और बढ़ गया. ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में हाथियों की लगातार मौजूदगी के बावजूद वन विभाग द्वारा न तो समय पर कोई चेतावनी जारी की जाती है और न ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाते हैं. उनका कहना है कि यदि पहले से सूचना दी जाती, तो शायद इस तरह की घटना को टाला जा सकता था। पिछले छह महीनों में यह दूसरी बड़ी घटना है, जिसमें हाथी के हमले से किसी की जान गई है. ग्रामीणों की है कि हाथियों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई जाए, समय-समय पर चेतावनी जारी की जाए और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, इसके अलावा उन्होंने प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की भी मांग की।

हवाई सेवा विस्तार पर सुनवाई जुलाई तक टली, नई एयरलाइंस को फिलहाल नहीं बुलाएगी सरकार

बिलासपुर, 21 अप्रैल (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ में चल रही बिलासपुर में हवाई सुविधा विस्तार से संबंधित जनहित याचिकाओं की सुनवाई जुलाई के अंतिम सप्ताह तक के लिए टाल दी गई.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर हवाई सुविधा विस्तार के मामले में लगातार मॉनिटरिंग कर विभिन्न आदेश देता आया है, जिससे बिलासपुर में हवाई सुविधा विस्तार संबंधी कई कार्य समय पर हुए हैं. आज की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास ने दाखिल किए गए शपथ पत्र का ब्यौरा देते हुए बताया कि रनवे कारपेटिंग बाउंड्री वॉल आदि कार्य सैक्शन है और शुरुआत से अभी तक लगभग 100 करोड़ रुपए बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास में खर्च किए जा चुके हैं. जहां तक नई उड़ानों का प्रश्न है राज्य सरकार एलाइंस एयर को सब्सिडी दे रही है पर निजी एयरलाइंस कंपनियों को बिलासपुर से उड़ान शुरू करने के लिए कोई आमंत्रण नहीं दिया गया. अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि, व्यावसायिक स्तर पर एयरलाइंस चाहे तो बिलासपुर से फ्लाइट संचालन कर सकती है उसमें कोई रोक नहीं है लेकिन जहां तक सब्सिडी का प्रश्न है तो यह केवल सरकारी कंपनी को दिया जा रहा है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि, जब केंद्र सरकार उड़ान योजना में सब्सिडी देने के माध्यम से ओपन टेंडर कर सकती है और निजी एयरलाइंस समेत सभी एयरलाइंस को आमंत्रित कर सकती है तो यही कार्य राज्य सरकार भी कर सकती है और उसे इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, इस प्रस्ताव को भी राज्य सरकार की ओर से स्वीकार नहीं किया गया और कहा गया कि निजी एयरलाइंस कंपनी चाहे तो कमर्शियल उड़ान संचालित करें.

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी याचिकाओं में मांगे गए अनुतोष की जांच की और कहा कि, याचिकाएं 4 सी एयरपोर्ट के लिए ही लगाई गई है. इस स्तर पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि, याचिकाओं की सुनवाई जारी रहे इस पर राज्य सरकार आपत्ति नहीं करेगी. परंतु उसे लंबा समय दिया जाए जिससे कि वह इस मामले में कुछ ठोस प्रगति कर न्यायालय को बता सके और सुनवाई को अगस्त माह तक टालने की मांग की. राज्य सरकार के आश्वासन पर विचार कर हाईकोर्ट ने जनहित याचिकाओं की सुनवाई जुलाई अंतिम सप्ताह तक के लिए टाल दी. उस समय तक हुई प्रगति के संबंध में राज्य सरकार एक नया शपथ पत्र दाखिल करेगी।

मोदी सरकार अपनी विफलता से ध्यान हटाने महिला आरक्षण का मुद्दा उठाया: भूपेश बघेल

रायपुर, 21 अप्रैल (हाईवे चैनल)। पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जनहित के मुद्दों तथा सरकार की विफलता से ध्यान हटाने भाजपा ने महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रही है। सिलेंडर की कमी, पेट्रोल, डीजल, खाद-बीज की कमी, खाद्य पदार्थों के दाम, बढ़ती महंगाई, एफस्टीन फाईल जैसे मुद्दों के कारण मोदी सरकार की साख गिर चुकी है। इसीलिए ये जनता का मूल समस्याओं से ध्यान हटाना चाह रहे।

पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023) 128 वां संविधान संशोधन सितंबर 2023 में संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु इस पर हस्ताक्षर कर चुकी है तथा यह कानून भी बन चुकी है। भाजपा 2023 के आरक्षण बिल को क्यों लागू नहीं कर रही है? इस बिल के आधार पर तुरंत आरक्षण प्रभावी हो सकता है। भाजपा ने 16 अप्रैल 2026 को जो विधेयक संसद में प्रस्तुत किया 131 वां संविधान संशोधन अधिनियम इसमें महिला आरक्षण के संदर्भ में नहीं भाजपा महिला आरक्षण को मुखौटा बनाकर परिसीमन संशोधन बिल तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल को पास करवाना चाहती थी। पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को यदि तुरंत लागू करना है तो परिसीमन का इंतजार किए बिना वर्तमान सदस्य संख्या में ही 33 प्रतिशत का आरक्षण क्यों नहीं देना चाहती सरकार? कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल इसके लिए तैयार है।

महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो चुका है

पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा जो परिसीमन चाहती है उसमें छत्तीसगढ़ सहित छोटे राज्य जिनकी वर्तमान सदस्य संख्या कम है उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। भाजपा अपनी राजनीतिक फायदे के हिसाब से परिसीमन चाह रही है। पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार 2023 के महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन कर महिला आरक्षण को तुरंत लागू कर सकती थी उसने ऐसा क्यों नहीं किया? जबकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो कानून बन चुका है 2034 से मूर्त रूप लेगा संशोधन से तुरंत लागू हो जाता। भाजपा की मंशा महिला आरक्षण की नहीं अपने मनमुताबिक सीटों के परिसीमन की थी जो विपक्षी दलों की एकजुटता से पूरा नहीं हो चुका।